संख्या-21/2015/29/71-2-15-एस-20/2009

प्रेषक,

अरिन्दम भट्टाचार्य,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान,
सैफई इटावा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 09 फरवरी, 2015**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2014-15 में पैरामेडिकल विज्ञान महाविद्यालय के अतिरिक्त आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2535/रिम्सएण्डआर/2014-15 दिनांक 07 नवम्बर, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में पैरामेडिकल विज्ञान महाविद्यालय के अतिरिक्त आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु रू0 58,78,86,000/- की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 18,82,53,000/- (रूपया अठारह करोड़ बयासी लाख तिरपन हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1. **स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/डाकघर/बैंक में नहीं रखी जायेगी। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी संस्थान की होगी।**
2. **प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु स्वीकृत की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसकी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।**
3. **वित्त बजट अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 जुलाई 2014 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**
4. **कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी संस्थान/कार्यदायी संस्था की होगी।**
5. **प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा।**
6. **संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।**
7. **कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।**
8. **आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।**
9. **संस्थान द्वारा समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।**
10. **प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।**
11. **प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार संस्थान द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।**
12. **प्रायोजना में प्रस्तावित 1.20 मी0 कुर्सी तल की ऊँचाई तथा छत की अतिरिक्त ऊँचाई 1.30 मी0 अर्थात कुल छत की ऊँचाई 4.20 मी0 तथा आवासीय एवं अनावासीय भवनों में ग्रिट फिनिश, पेविट टाइल्स, स्ट्रक्चरल क्चरल ग्लेजिंग, वुडन फ्लोरिंग, वाल पैनलिंग एवं हाईल्युमिनियम लाइट कार्यमदें उच्च विशिष्टि श्रेणी के है।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

13. संस्थान द्वारा प्रायोजना में प्रस्तावित प्रोपराइटरी श्रेणी के कार्यो पर व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अंतर्गत किया जायेगा।
14. प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत् मानते हुए लागत का आंकलन किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैस-नये कार्य बढाना, ड्राइंग एवं डिजाइन में परिवर्तन, अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर संस्थान द्वारा 03 माह के अंदर समिति का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
15. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
16. उक्त कार्य की वर्तमान तभा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो इसे संस्थान अपने स्तर से सुनिश्चित करेगा। माज्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/संस्थान की होगी।

2- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, आर0आई0एम0एस0, सैफई इटावा द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक-"4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा,शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-08-रूरल इंस्टीटयूट आफ मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च सैफई इटावा में पैरा मेडिकल इंस्टीटयूट की स्थापना-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/231/दस-2015, दिनांक 09 फरवरी, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(अरिन्दम भट्टाचार्य)
विशेष सचिव।

संख्या-21/2015/29(1)/71-2-14-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, इटावा।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त अधिकारी, आर0आई0एम0एस0, सैफई इटावा।
5. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
6. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दुबे)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in